गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 317
दि. 21.03.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

राज्य सरकार के दिशा-निर्देशन में गुजरात में एलपीजी का पर्याप्त भंडार, अब कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं

राज्य में एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध : व्हॉट्सएप, मिस्डकॉल, एसएमएस, ऑनलाइन बुकिंग तथा स्मार्टफोन ऐप से होगी बुकिंग

(जीएनएस)। गांधीनगर : राज्य सरकार के कहे अनुसार राज्य में रसोई गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और इस संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। गैस एजेंसियों की ओर से एलपीजी सिलेंडर की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक देखरेख रखी जा रही है और नागरिकों को उनके सिलेंडर के लिए एजेंसी पर जाकर कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा नागरिकों को उनके घर पर ही सरलता से सिलेंडर उपलब्ध हो; इसके लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग से पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

नागरिकों को मोबाइल के एक क्लिक से ही सिलेंडर मिले; इसके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा सभी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। एलपीजी बुकिंग तथा रीफिल के लिए पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और पंजीकृत लाभार्थी व्हॉट्सएप, मिस्डकॉल, एसएमएस/आईवीआर बुकिंग, स्मार्टफोन एप्लिकेशन तथा कंपनी के अधिकृत पोर्टल का उपयोग करके आसानी से बुकिंग करवा सकते हैं।

आईओसीएल की बुकिंग सुविधाएँ

आईओसीएल के अनुसार मोबाइल द्वारा एलपीजी बुकिंग के लिए निम्नानुसार सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। बुकिंग के बाद सरलता से सिलेंडर की होम डिलीवरी हो जाएगी।

व्हॉट्सएप के लिए : 7588888824
एसएमएस / आईवीआरएस : 7718955555
मोबाइल ऐप : IndianOil ONE
ऑनलाइन पोर्टल : https://cx.indianoil.in

एचपी गैस की बुकिंग के लिए निम्न सुविधाएँ उपलब्ध हैं

व्हॉट्सएप के लिए : 9222201122
रजिस्टर्ड नंबर द्वारा कॉल से बुकिंग के लिए : 9493602222
SMS / IVRS बुकिंग के लिए: 8888823456
मोबाइल ऐप : HP PAY
ऑनलाइन पोर्टल : https://myhpgas.in

भारत गैस द्वारा आसान बुकिंग सुविधाएँ

व्हॉट्सएप के लिए : 1800224344
रजिस्टर्ड नंबर द्वारा कॉल से बुकिंग के लिए : 7710955555
SMS / IVRS बुकिंग के लिए : 7715012345
मोबाइल ऐप : HelloBPCL
ऑनलाइन पोर्टल : my.ebharatgas.com

इसके अलावा; पार्टनर वॉलेट तथा बैंकिंग ऐप की मदद से भारत बिल पेमेंट सिस्टम द्वारा गैस सिलेंडर की बुकिंग कराई जा सकती है। इन सभी बुकिंग्स में सुव्यवस्थित डिजिटल सिस्टम का अनुकरण किया जाता है और एसएमएस द्वारा उपभोक्ता को कन्फर्मेशन भेजा जाता है। घरेलू गैस कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के साथ डिलीवरी दी जाती है। राज्य में एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और बफर स्टॉक में भी निरंतर वृद्धि हो रही होने के कारण किसी भी नागरिक के लिए सरलता से घर बैठे ही डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है।

समय पर डिलीवरी मिल जाती है, कोई समस्या नहीं है : उपभोक्ता

खेडा जिले में ठासरा के निवासी महिपालसिंह प्रतापसिंह परमार ने कहा कि इंडेन गैस के सिलेंडर नियमित रूप से मिल रहे हैं। गाइडलाइन के अनुसार उनकी सर्विस अच्छी है और किसी भी प्रकार की तकलीफ के बिना समय पर डिलीवरी दी जाती है। अन्य एक उपभोक्ता परेशभाई वोरा ने कहा कि हाल में सर्विस में कोई समस्या नहीं है। बुकिंग कराने के बाद समय पर सिलेंडर मिल जाता है। कालसर गाँव के नाजिमखान नबीखान पठान ने कहा कि उन्हें आसानी से सिलेंडर मिल जाता है और वैध तरीके से डिलीवरी हो रही है। मोडासा में खुशी एचपी गैस एजेंसी के संचालक श्री हरिश्चंद्र भाटी ने कहा कि सरकार की ओर से पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। प्रतिदिन गाड़ियाँ स्टॉक लेकर आती हैं। उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड नंबर से बुकिंग करा सकते हैं और दो दिन में उन्हें डिलीवरी मिल जाएगी। इस स्थिति में किसी को अफवाहों से पैनिक होने की जरूरत नहीं है।

एलपीजी वितरण की कड़ी निगरानी के लिए अधिकारियों की नियुक्ति

राज्य की सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तथा निजी गैस एजेंसियों में कड़ी निगरानी तथा मॉनिटरिंग के लिए राजस्व एवं पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नागरिकों को समय पर एलपीजी आपूर्ति मिले और अनियमितता को रोका जा सके।

एलपीजी के लिए हेल्पलाइन नंबर

राज्य में एलपीजी संबंधी किसी भी समस्या के लिए नागरिकों से राज्य हेल्पलाइन नंबर 1800-233-0222 पर संपर्क करने को कहा गया है। राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नागरिकों को अधिकृत रूप से सटीक जानकारी मिलती रहे।

संपादकीय

खौफ का खेल

सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर शहर चंडीगढ़ कुछ समय पहले तक, अपनी चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिये मशहूर रहा है। इस शहर को लंबे समय तक हिंसा व अपराधों से सुरक्षित माना जाता रहा है। लेकिन विडंबना है कि अब यह तेजी से असुरक्षित होता जा रहा है। पिछले दिनों चंडीगढ़ का पॉश इलाका माने जाने वाले सेक्टर नौ में एक युवा प्रॉपर्टी डीलर की दिनदहाड़े हुई चौंकाने वाली हत्या ने शहर की शांति व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाया। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा की सावधानीपूर्वक बनायी गई इस केंद्रशासित प्रदेश की छवि को धूमिल किया है। निस्संदेह, इस केंद्र शासित प्रदेश के सबसे समृद्ध और सुरक्षित इलाकों में से एक सेक्टर में, इस तरह की सरेआम निर्मम हत्या होना न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह बेहद गंभीर अपराध बढ़ने का संकेत भी देता है। शुरुआती रिपोर्टों में इस अपराध को गैंगस्टरों की आपसी दुश्मनी से जोड़ कर देखा जा रहा है। जिसमें लकी पटियाला और बबीहा गैंग जैसे नामों का जिक्र सामने आया है। यह हत्याकांड एक चिंताजनक प्रवृत्ति को रेखांकित करता है कि अब संगठित अपराध उन शहरी केंद्रों में लगातार बढ़ रहे हैं, जिन्हें कभी इस तरह की गैंगवार से अछूता समझा जाता था। माना जाता रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस यथाशीघ्र अपराध की जड़ तक पहुंचकर अपराधियों पर शिकंजा कसने में सफल रहती है। यह चौंकाने वाली बात है कि हाल के वर्षों में पंजाब में गैंगवार में होने वाली हिंसा और जबरन वसूली के रैकेट में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। जिसका सबसे प्रमुख उदाहरण मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या है। निस्संदेह, सेक्टर नौ में दिनदहाड़े हुई हत्या से साल 2017 में हुए आकांक्षा सेन हत्याकांड की टीस एक बार फिर उभर आई। यह भी एक ऐसा ही हाई-प्रोफाइल मामला था। जिसमें न्याय मिलने में लगातार हुई देरी के कारण आज भी लोगों के मन में गहरी कसक व्याप्त है। निस्संदेह, दोनों ही हत्याकांडों से जुड़ी समानताएं चिंता बढ़ाने वाली हैं। मसलन, अपराध सार्वजनिक रूप से हुए हैं। जिससे अपराध को रोकने की पुलिस की क्षमता पर सवाल उठाए गए हैं। इसमें एक सवाल जवाबदेही का भी है। वास्तव में इस तरह सरेआम दिन दहाड़े होने वाले अपराध सार्वजनिक विमर्श में कई संवेदनशील सवालों को जन्म देते हैं। इस घटना से जुड़ा सबसे चिंताजनक पहलू है हत्याकांड में शामिल रहे अपराधियों का दुस्साहस। निर्विवाद रूप से सार्वजनिक स्थल के बाहर दिन-दहाड़े की गई हत्या बताती है कि ये अपराधियों में कानून-व्यवस्था के प्रति डर समाप्त होने का संकेत है। जिसके परिणामस्वरूप कानून प्रवर्तन की निवारक क्षमता कमजोर हो जाती है। निस्संदेह, इस तरह की घटनाओं को लेकर खुफिया जानकारी जुटाने, पुलिस समन्वय और ऐसे हमलों को रोकने की क्षमता पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। कोई शक नहीं कि चंडीगढ़ को अब किसी भी तरह की लापरवाही का शिकार बनने नहीं दिया जा सकता। प्रशासन को प्रतिक्रियात्मक पुलिसिंग के बजाय सक्रिय और खुफिया जानकारी आधारित रणनीति अपनानी होगी। निश्चित रूप से ऐसे अपराधों पर तभी अंकुश लगाना संभव हो पाएगा, जब पुलिस का लक्ष्य आपराधिक गिरोहों, उनकी आर्थिक मदद करने वालों तथा उनके सहयोगियों के गठजोड़ को नेस्तनाबूद करना होगा। इसमें दो राय नहीं कि आपराधिक मामलों में तुरंत जांच, पुलिस की प्रत्यक्ष उपस्थिति और समय पर न्याय मिलने से न केवल जनता का विश्वास बहाल होगा, बल्कि शहरों को आने वाले समय में ऐसे गैंगवार से जुड़ी हिंसा से भी बचाया जा सकेगा। निस्संदेह, नई तकनीक और इंटरनेट आधारित आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये हाइटैक पुलिस की जरूरत होगी। नई तकनीक जहां अपराधियों का हथियार बनती है, वहीं उन पर शिकंजा कसने में मददगार हो सकती है। बशर्ते इन संसाधनों का उपयोग सावधानी व तत्परता से किया जाए। तब अपराधियों की गैंगवार पर नकेल डालने में खुफिया जानकारी और आधुनिक तकनीक खासी मददगार हो सकती हैं। सिटी ब्यूटीफुल में कानून व्यवस्था की खूबसूरती बचाने के लिये जरूरी कदम उठाने की सख्त जरूरत है। निस्संदेह, यही वक्त की मांग भी है।

ईरान वार पर वार किये जा रहा है मगर खाड़ी देश पलटवार की हिम्मत तक नहीं दिखा पा रहे

> सबसे खतरनाक बात यह है कि अब ऊर्जा खुद एक हथियार बन चुकी है। गैस संयंत्र, तेल क्षेत्र और बंदरगाह अब सैन्य निशाने हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो दुनिया को एक ऐसे ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है जो पहले कभी नहीं देखा गया।

तेल, गैस और बारूद की गंध अब एक साथ हवा में तैर रही है। पश्चिम एशिया में भड़की जंग ने दुनिया को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर अगला दिन एक नए खतरे का संकेत दे रहा है। यह सिर्फ दो देशों के बीच का टकराव नहीं रहा, बल्कि पूरी वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था को सीधे निशाने पर ले आया है। देखा जाये तो इजराइल ने जब ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमला किया, तो यह सीधा उस नस पर वार था जिससे पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति चलती है। जवाब में ईरान ने भी देर नहीं की और कतर के रास लफ्फान गैस केंद्र को निशाना बना दिया। यह वही केंद्र है जो दुनिया की कुल गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा संभालता है। यानी अब जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि दुनिया की रसोई और उद्योगों तक पहुंच चुकी है।

तेल बाजार में हाहाकार मच गया। कीमतें अचानक उछलकर एक सौ बीस डॉलर के करीब पहुंच गईं। यह सिर्फ आर्थिक उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि उस डर का इजहार था कि फारस की खाड़ी अब बारूद का ढेर बन चुकी है, जहां से किसी भी वक्त पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है।

इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब-सा दोहरा रुख अपनाया। एक तरफ उन्होंने कहा कि अमेरिका का इस हमले से कोई लेना देना नहीं, दूसरी तरफ ईरान को खुली चेतावनी दे डाली कि अगर कतर पर दोबारा हमला हुआ तो साउथ पार्स को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। यहीं से कहानी और पेचीदा हो जाती है। अब तक अमेरिका और इजराइल एक ही पाले में नजर आते थे, लेकिन अब दोनों के मकसद अलग अलग दिखने लगे हैं। ट्रंप एक कारोबारी की तरह सोचते हैं, वह ईरान पर दबाव बनाकर उसे अपने हिसाब से झुकाना चाहते हैं। लेकिन इजराइल की मंशा इससे कहीं आगे है, वह ईरानी शासन को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। यह दरार अब अमेरिका के भीतर भी दिखने लगी है। ट्रंप के अपने समर्थक सवाल कर रहे हैं कि क्या अमेरिका किसी और की लड़ाई में उलझता जा रहा है।

दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अब वह पीछे हटने वाला नहीं है। उसके विदेश मंत्री ने खुले शब्दों में कहा है कि अगर दोबारा उसके ऊर्जा ढांचे पर हमला हुआ तो वह बिना किसी संयम के पूरी ताकत से जवाब देगा। हम आपको बता दें कि ईरान ने सिर्फ कतर ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन तक को अपने निशाने पर ले लिया है। मिसाइलें और ड्रोन अब पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। हर हमला यह संकेत दे रहा है कि जंग अब फैल चुकी है और इसे रोकना आसान नहीं होगा। खाड़ी देशों की स्थिति सबसे ज्यादा नाजुक हो गई है। एक तरफ वह ईरान की कार्रवाई से नाराज हैं, दूसरी तरफ उन्हें डर है कि अगर वह सीधे युद्ध में उतर गए तो अमेरिका कभी भी पीछे हट सकता है और वह अकेले पड़ जाएंगे। हालांकि सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो वह सैन्य कार्रवाई करेगा। उधर, कतर ने ईरानी अधिकारियों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। लेकिन इन सबके बीच एक अनकहा डर साफ दिखता है, यानि कोई भी देश पूरी तरह इस आग में कूदने को तैयार नहीं है।

सबसे खतरनाक बात यह है कि अब ऊर्जा खुद एक हथियार बन चुकी है। गैस संयंत्र, तेल क्षेत्र और बंदरगाह अब सैन्य निशाने हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो दुनिया को एक ऐसे ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है जो पहले कभी नहीं देखा गया। यह संकट सिर्फ पेट्रोल या गैस की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर हर घर, हर उद्योग और हर देश पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, आपूर्ति टूटेगी और अर्थव्यवस्थाएं हिल जाएंगी। अब सवाल यही है कि क्या इस आग को बुझाने का कोई रास्ता बचा है। सच यह है कि इस समय केवल अमेरिका ही ऐसा देश है जिसके पास दोनों पक्षों को रोकने की ताकत है। लेकिन क्या ट्रंप ऐसा करना चाहते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर अमेरिका बिना शर्त इजरायल का साथ देता रहा तो यह संघर्ष पूरी तरह ऊर्जा युद्ध में बदल जाएगा। लेकिन अगर वह दूरी बनाकर किसी समझौते की राह निकालता है, तभी हालात संभल सकते हैं।

बहरहाल, एक चीज साफ दिख रही है कि कूटनीति नाकाम होती जा रही है। बातचीत की जगह अब धमाके सुनाई दे रहे हैं। हर देश अपनी ताकत दिखाने में लगा है, लेकिन कोई भी यह नहीं सोच रहा कि इसका अंत कहां होगा। अगर अब भी दुनिया नहीं संभली तो अगला संकट सिर्फ ऊर्जा का नहीं होगा, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिला देने वाला होगा। खाड़ी में लगी आग दूर बैठे देशों को भी झुलसा देगी। और तब शायद संभलने का मौका ही नहीं बचेगा।

प्रेरणा

संघर्ष की राख से उठी प्रतिभा: मैक्सिम गोर्की की प्रेरक गाथा

कभी-कभी जीवन की सबसे कठोर परिस्थितियाँ ही इंसान के भीतर छिपी असाधारण क्षमता को उजागर करती हैं। इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है, जहाँ विपरीत हालातों ने साधारण व्यक्तियों को असाधारण बना दिया। मैक्सिम गोर्की की जीवन कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो यह सिखाती है कि यदि मन में सीखने की ललक और आगे बढ़ने का जुनून हो, तो अभाव और कठिनाइयाँ भी सफलता के मार्ग में बाधा नहीं बन सकतीं।

सोवियत रूस की धरती पर जन्मे इस बालक का बचपन किसी सामान्य बच्चे की तरह सुखद नहीं था। बहुत कम उम्र में ही उसने अपने माता-पिता को खो दिया, जिससे जीवन की जिम्मेदारियाँ अचानक उसके कंधों पर आ गईं। उसकी बूढ़ी दादी ही उसका एकमात्र सहारा थीं, जिनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी उसी के हिस्से में आई। आर्थिक तंगी इतनी गहरी थी कि उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और जीविका चलाने के लिए एक कबाड़ी के यहाँ काम करना पड़ा। यह वह समय था, जब अधिकांश बच्चे खेलते-कूदते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके हिस्से में संघर्ष और जिम्मेदारियाँ ही आईं।

कबाड़ी की दुकान पर काम करना आसान नहीं था। दिनभर रद्दी और पुराने सामानों के बीच काम करते हुए शरीर थक जाता, लेकिन मन में ज्ञान की प्यास कभी कम नहीं हुई। वहाँ आने वाली रद्दी में अक्सर पुरानी किताबें भी होती थीं, जिन्हें लोग बेकार समझकर बेच देते थे। लेकिन वही किताबें उस बालक के लिए अनमोल खजाना बन गईं। वह अपने काम के बीच-बीच में उन किताबों को पढ़ता, उनके शब्दों में डूब जाता और एक नई दुनिया की कल्पना करता। यह पढ़ाई किसी स्कूल या शिक्षक के मार्गदर्शन में नहीं थी, बल्कि यह पूरी तरह से आत्मप्रेरणा और जिज्ञासा का परिणाम थी।

जब भी उसे किसी पुस्तक का कोई अंश समझ में नहीं आता, तो वह झिझकता नहीं था। वह कबाड़ी से पूछता, ग्राहकों से सवाल करता और तब तक जिज्ञासा शांत नहीं करता, जब तक उसे संतोषजनक उत्तर न मिल जाए। यही जिज्ञासा धीरे-धीरे उसके ज्ञान को गहराई देती गई। उसने यह साबित कर दिया कि शिक्षा केवल विद्यालयों तक सीमित नहीं होती, बल्कि सीखने की इच्छा ही सबसे बड़ा शिक्षक होती है। उसके लिए हर किताब एक नया शिक्षक थी और हर प्रश्न एक नया अवसर।

समय के साथ उसकी समझ और विचारों में परिपक्वता आने लगी। वह केवल पढ़ने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने अपने विचारों को शब्दों में ढालना भी शुरू कर दिया। उसने अपने अनुभवों, अपने संघर्षों और समाज के प्रति अपने दृष्टिकोण को लेखों के रूप में लिखना शुरू किया और उन्हें स्थानीय अखबारों को भेजने लगा। शुरुआत में यह प्रयास केवल एक प्रयोग जैसा था, लेकिन जब उसके लेख प्रकाशित होने लगे, तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह पहली बार था जब उसे लगा कि उसकी आवाज़ सुनी जा रही है और उसके विचारों का महत्व है।

अखबारों के संपादकों से मिले प्रोत्साहन ने उसके आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत कर दिया। उन्होंने उसकी लेखनी की सराहना की और उसे आगे लिखने के लिए प्रेरित किया। यह प्रोत्साहन उसके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। धीरे-धीरे उसने लेखन को अपना माध्यम बना लिया, जिसके जरिए वह समाज की सच्चाइयों को उजागर करने लगा। उसके शब्दों में एक अलग ही शक्ति थी, जो सीधे पाठकों के दिल तक पहुँचती थी।

समय बीतता गया और वही बालक, जिसने कभी कबाड़ी की दुकान पर काम करते हुए रद्दी में मिली किताबों से ज्ञान अर्जित किया था, एक महान लेखक के रूप में उभरकर सामने आया। मैक्सिम गोर्की ने साहित्य की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी रचनाएँ केवल कहानियाँ नहीं थीं, बल्कि वे समाज के उस वर्ग की आवाज़ थीं, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से गरीबों, मजदूरों और संघर्षरत लोगों के जीवन को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया।

उनकी प्रसिद्ध कृति मां आज भी विश्व साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह उपन्यास केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक है, जिसमें समाज के परिवर्तन और मानवता के संघर्ष को दर्शाया गया है। इस रचना ने न केवल साहित्य जगत को समृद्ध किया, बल्कि पाठकों को भी सोचने पर मजबूर किया कि समाज में समानता और न्याय कितना आवश्यक है।

गोर्की की जीवन यात्रा यह स्पष्ट करती है कि सफलता केवल संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिकता और दृढ़ संकल्प पर आधारित होती है। उन्होंने अपने जीवन में जितनी कठिनाइयों का सामना किया, उतनी ही मजबूती से उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि परिस्थितियाँ उनके खिलाफ हैं, बल्कि उन्होंने हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखा।

उनकी कहानी आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी उस समय थी। आज भी कई लोग आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन यदि वे गोर्की की तरह अपने भीतर की जिज्ञासा और सीखने की ललक को बनाए रखें, तो वे भी अपनी राह बना सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान का कोई विकल्प नहीं होता और जो व्यक्ति ज्ञान के प्रति समर्पित होता है, वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है।

अंततः, मैक्सिम गोर्की की यह प्रेरक गाथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आएँ, यदि हमारे भीतर आगे बढ़ने की इच्छा और आत्मविश्वास हो, तो हम किसी भी ऊँचाई को छू सकते हैं। उनकी कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि यह मानव आत्मा की अटूट शक्ति और संघर्ष की विजय का प्रतीक है, जो हर युग में लोगों को प्रेरित करती रहेगी।

एक वोट का वजन और घर की दरारें

हरियाणा के हालिया राज्यसभा चुनाव ने एक पुरानी लेकिन अक्सर भुला दी जाने वाली सच्चाई को फिर सामने ला दिया है। लोकतंत्र में कोई भी जीत 'छोटी' नहीं होती और कोई भी चूक 'मामूली' नहीं होती। महज 0.34 वोट के अंतर से तय हुआ परिणाम केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हमारी राजनीति के बदलते चरित्र का संकेत है।

पहली नजर में यह चुनाव एक साधारण गणित जैसा दिखता था। विधानसभा में संख्या संतुलन ऐसा था कि एक सीट भाजपा और एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ा, यह साफ हो गया कि अब राजनीति केवल अंकगणित नहीं रही; यह रणनीति, मनोविज्ञान और प्रबंधन का जटिल मिश्रण बन चुकी है।

भाजपा द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल को समर्थन देकर मैदान में उतारना इसी बदलाव का प्रतीक था। यह कदम जीतने से ज्यादा विपक्ष को अस्थिर करने की कोशिश था और इस मायने में वह सफल भी रही। कांग्रेस के भीतर हुई क्रॉस वोटिंग ने यह साबित कर दिया कि राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी चुनौती अब विपक्ष नहीं, बल्कि अपने ही घर के भीतर पैदा हो रही दरारें हैं।

कांग्रेस के लिए यह परिणाम जितना राहत देने वाला है, उतना ही असहज करने वाला भी। जीत दर्ज हो गई, लेकिन जिस तरह यह जीत किनारे पर जाकर मिली, उसने संगठन की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी। पांच विधायकों का पार्टी लाइन से हटकर मतदान करना केवल असंतोष का संकेत नहीं, बल्कि संवादहीनता और नेतृत्व की सीमाओं की ओर भी इशारा करता है। राज्यसभा चुनाव में व्हिप लागू न होने की संवैधानिक व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए यह एक नैतिक कसौटी जरूर बन जाती है।

इस पूरे घटनाक्रम में यदि कोई पक्ष अपने कौशल के कारण उभरकर सामने आया है, तो वह है चुनावी प्रबंधन। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस चुनाव में कांग्रेस की जीत उसके संख्याबल से ज्यादा उसके प्रबंधन की जीत है। संकट की स्थिति में नेतृत्व का सक्रिय होना, विधायकों को एकजुट रखना और संभावित नुकसान को सीमित करना, ये सभी तत्व इस बात को रेखांकित करते हैं कि आज की राजनीति में संगठनात्मक पकड़ कितनी निर्णायक हो गई है। लेकिन यही स्थिति एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्या राजनीतिक दल अब संस्थागत मजबूती के बजाय व्यक्तित्व-आधारित प्रबंधन पर निर्भर होते जा रहे हैं? यदि किसी एक नेता की सक्रियता से ही जीत और हार तय हो रही है, तो यह दीर्घकाल में संगठन के लिए कितना टिकाऊ मॉडल है? उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया भी इस चुनाव में चर्चा का विषय रही। जब केंद्रीय नेतृत्व स्थानीय समीकरणों को नजरअंदाज कर निर्णय लेता है, तो वह केवल एक नाम तय नहीं करता, बल्कि संगठन के भीतर संदेश भी भेजता है। कांग्रेस नेतृत्व ने भी तो एकदम नये कर्मवीर बौद्ध को प्रत्याशी बनाकर बैठे-बिठाए विधायकों की नाराजगी मोल ली। यह चुनाव उस निर्णय की परीक्षा था, जिसमें सफलता तो मिली, लेकिन वह सहज नहीं थी। यह संकेत है कि जमीनी राजनीति को समझे बिना लिए गए फैसले हमेशा जोखिम के साथ आते हैं।

इस चुनाव का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा, वह था रद्द हुए वोट। तकनीकी कारणों से अमान्य हुए वोटों ने यह दिखाया कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कितनी संवेदनशील होती हैं। एक छोटी-सी प्रक्रिया संबंधी गलती, जो सामान्य परिस्थितियों में नजरअंदाज हो सकती है, यहां निर्णायक बन गई। यह केवल राजनीतिक दलों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे चुनावी तंत्र के लिए भी एक सीख है। आमतौर पर जान-बूझकर वोट रद्द करवाने की परंपरा भी रही है। ऐसा अकेले हरियाणा ही नहीं, दूसरे सूबों में भी अकसर देखा गया है।

हरियाणा की राजनीति में निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका भी इस बार फिर रेखांकित हुई। भले ही वे जीत नहीं सके, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि तीसरा विकल्प केवल औपचारिकता नहीं होता। यह उस राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है, जहां व्यक्तिगत समीकरण और अवसरवादिता दलगत सीमाओं को चुनौती देते रहते हैं। चुनाव के बाद जिस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हरियाणा विधानसभा में हंगामा, आरोप-प्रत्यारोप और संगठनात्मक कार्रवाई की चेतावनियां के रूप में सामने आई, वे भी इस बात का संकेत हैं कि यह परिणाम केवल एक चुनावी घटना नहीं, बल्कि आने वाले समय की राजनीति को प्रभावित करने वाला मोड़ है।

भाजपा के लिए यह चुनाव यह संदेश लेकर आया है कि रणनीतिक आक्रामकता से वह विपक्ष को असहज कर सकती है, भले ही हर बार जीत हासिल न हो। वहीं कांग्रेस के लिए यह स्पष्ट चेतावनी है कि केवल संख्याबल पर्याप्त नहीं है, संगठनात्मक एकजुटता और आंतरिक विश्वास ही उसकी असली ताकत हो सकते हैं। आखिरकार, 0.34 वोट का यह अंतर हमें उस मूल प्रश्न की ओर वापस ले जाता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लोकतंत्र की असली शक्ति क्या है? यह केवल बहुमत का खेल नहीं, बल्कि विश्वास, अनुशासन और जिम्मेदारी का तंत्र है।

हरियाणा का यह चुनाव हमें यही याद दिलाता है कि लोकतंत्र में परिणाम आखिरी क्षण तक तय नहीं होते। और जब फैसला होता है, तो वह केवल जीत या हार नहीं होता, वह एक संदेश होता है। संदेश यह कि राजनीति में अब केवल संख्या नहीं, बल्कि संबंध, रणनीति और समय पर लिए गए फैसले ही असली फर्क पैदा करते हैं। और कांग्रेस की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि पार्टी को आगे भी तैयार रहना होगा।

अभियान

नाम जप का रहस्य: क्यों 'राधे-कृष्ण' और 'हर-हर महादेव' है प्रचलित, जबकि 'कृष्ण-कृष्ण' और 'शिव-शिव' कम सुनाई देता है

भारतीय सनातन परंपरा में भक्ति का सबसे सरल और प्रभावशाली माध्यम नाम जप को माना गया है। यह एक ऐसी साधना है, जिसमें किसी विशेष विधि, स्थान या समय की बाध्यता नहीं होती, फिर भी इसका प्रभाव अत्यंत गहरा और व्यापक होता है। माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति बड़े यज्ञ, तप या अनुष्ठान करने में सक्षम नहीं है, तो वह केवल ईश्वर के नाम का स्मरण करके भी उसी प्रकार का पुण्य और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अभिवादन के रूप में भी भगवान के नाम का उपयोग किया जाता है, जैसे 'राम-राम', 'राधे-राधे' और 'हर-हर महादेव'। यह केवल एक सांस्कृतिक परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक अभ्यास है, जो हर व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ने का कार्य करता है।

इसी परंपरा के बीच एक जिज्ञासा अक्सर सामने आती है कि जब 'राम-राम' या 'राधे-राधे' जैसे नामों का दोहराव सहज और सामान्य है, तो 'कृष्ण-कृष्ण' या 'शिव-शिव' का उच्चारण उतना प्रचलित क्यों नहीं है। क्या यह किसी प्रकार का निषेध है या फिर इसके पीछे कोई गहरी धार्मिक और ज्योतिषीय समझ छिपी हुई है? इस प्रश्न का उत्तर हमें सनातन धर्म की गहराई, उसके दर्शन और उसकी परंपराओं को समझने में मदद करता है।

श्रीकृष्ण के संदर्भ में यह मान्यता प्रचलित है कि उनका नाम अकेले नहीं लिया जाता, बल्कि सदैव राधा के साथ जुड़ा होता है। 'राधे-कृष्ण' का उच्चारण केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक सिद्धांत को व्यक्त करता है। राधा को भक्ति, प्रेम और समर्पण का सर्वोच्च स्वरूप माना गया है, जबकि कृष्ण को परमात्मा का प्रतीक। इस प्रकार, जब कोई 'राधे-कृष्ण' कहता है, तो वह केवल भगवान को नहीं, बल्कि उस प्रेम और भक्ति को भी स्मरण कर रहा होता है, जो परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है।

धार्मिक ग्रंथों और भक्ति साहित्य में यह वर्णित है कि श्रीकृष्ण की कृपा तभी प्राप्त होती है, जब साधक पर राधा की कृपा होती है। यह विचार इस बात को दर्शाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए केवल ज्ञान या शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रेम और समर्पण की भी आवश्यकता होती है। इसी कारण 'कृष्ण-कृष्ण' के बजाय 'राधे-राधे' या 'राधे-कृष्ण' कहना अधिक उपयुक्त और प्रभावशाली माना गया है। यह केवल एक उच्चारण नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक है, जिसमें भक्ति और भगवान दोनों का समावेश होता है।

दूसरी ओर, शिव के नाम के उच्चारण को लेकर भी विशेष मान्यताएं प्रचलित हैं। शिव को सनातन धर्म में एक अद्वितीय और व्यापक स्वरूप के रूप में देखा जाता है। वे सृष्टि के संहारक होने के साथ-साथ करुणा, वैराग्य और तपस्या के प्रतीक भी हैं। उनका स्वरूप इतना गूढ़ और व्यापक है कि उन्हें केवल एक नाम या शब्द में सीमित करना कठिन माना जाता है। यही कारण है कि उनके लिए 'हर-हर महादेव' या 'ॐ नमः शिवाय' जैसे मंत्र अधिक प्रचलित हैं।

'हर-हर महादेव' का अर्थ केवल शिव की स्तुति करना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी दार्शनिक भावना को व्यक्त करता है कि हर व्यक्ति में महादेव का वास है। यह विचार अद्वैत दर्शन के सिद्धांत को दर्शाता है, जिसमें आत्मा और परमात्मा को एक ही माना गया है। जब कोई 'हर-हर महादेव' कहता है, तो वह केवल भगवान को नहीं, बल्कि अपने भीतर और हर जीव में स्थित दिव्यता को स्वीकार करता है।

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी 'शिव-शिव' के उच्चारण को लेकर कुछ विशेष तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, प्रत्येक अक्षर का एक विशेष संख्यात्मक मान होता है, जो एक विशेष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। 'श' और 'व' अक्षरों के मान को जोड़ने पर जो परिणाम प्राप्त होता है, उसे पंच तत्वों और पंच भूतों से संबंधित माना जाता है। पंच तत्व, अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, हमारे शरीर और इस सृष्टि के मूल आधार हैं।

यह माना जाता है कि 'शिव-शिव' का लगातार उच्चारण इन तत्वों की ऊर्जा को सक्रिय कर सकता है। चूंकि मानव शरीर स्वयं इन तत्वों से बना है, इसलिए वह इस ऊर्जा को एक सीमा तक सहन कर सकता है, लेकिन यदि यह ऊर्जा असंतुलित हो जाए, तो यह मानसिक और शारीरिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। इसी कारण पारंपरिक रूप से 'ॐ नमः शिवाय' जैसे मंत्र को अधिक संतुलित और सुरक्षित माना गया है। यह पंचाक्षरी मंत्र इन पांचों तत्वों को संतुलित करने का कार्य करता है और साधक के भीतर एक स्थिरता और शांति उत्पन्न करता है।

हालांकि, यह भी स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि ये सभी मान्यताएं पूर्णतः निषेधात्मक नहीं हैं। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें किसी भी प्रकार का कठोर नियम या बंधन नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा के साथ 'कृष्ण-कृष्ण' या 'शिव-शिव' का जाप करता है, तो उसकी भक्ति निश्चित रूप से स्वीकार की जाती है। यहां भावना और समर्पण को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, न कि केवल शब्दों के चयन को।

नाम जप का वास्तविक उद्देश्य मन को एकाग्र करना और उसे भटकाव से मुक्त करना है। जब व्यक्ति बार-बार किसी नाम का उच्चारण करता है, तो उसका मन धीरे-धीरे उस नाम के भाव में डूब जाता है। यह प्रक्रिया ध्यान की अवस्था उत्पन्न करती है, जिसमें व्यक्ति बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर की यात्रा पर निकल पड़ता है। यही कारण है कि नाम जप को एक प्रकार का ध्यान और साधना भी माना जाता है।

समय के साथ यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में भी स्थापित हो गई है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग अलग-अलग नामों का उपयोग अभिवादन के रूप में करते हैं। ब्रज क्षेत्र में 'राधे-राधे' कहना सामान्य है, जबकि उत्तर भारत के कई हिस्सों में 'राम-राम' का उपयोग होता है। शिव भक्तों के बीच 'हर-हर महादेव' का उद्घोष एक विशेष पहचान बन चुका है। यह सभी परंपराएं इस बात का प्रमाण हैं कि नाम जप केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि एक सामूहिक सांस्कृतिक धरोहर भी है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि 'कृष्ण-कृष्ण' और 'शिव-शिव' के उच्चारण को लेकर जो मान्यताएं प्रचलित हैं, वे धर्म, दर्शन, भक्ति और ज्योतिष के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम हैं। यह किसी प्रकार का कठोर निषेध नहीं, बल्कि एक परंपरागत समझ है, जिसका उद्देश्य साधना को संतुलित और प्रभावशाली बनाना है। इन मान्यताओं को समझकर यदि हम नाम जप करते हैं, तो यह हमारी भक्ति को और अधिक गहरा और सार्थक बना सकता है। भक्ति का मार्ग सदैव सरल और खुला होता है। इसमें किसी प्रकार की जटिलता या बाध्यता नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति के मन में सच्ची श्रद्धा और समर्पण है, तो वह किसी भी नाम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच सकता है। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, जो इसे अनंत, व्यापक और सर्वसमावेशी बनाती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में जल जीवन मिशन 2.0 अंतर्गत केन्द्र व राज्य सरकार के बीच महत्वपूर्ण एमओयू

▸▸ सरकार राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक नल से जल पहुँचाने के लिए कटिबद्ध : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ सरकार द्वारा किया गया यह एमओयू राज्य के पेयजल प्रबंधन एवं ग्रामीण जनजीवन के गुणात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा

▸▸ राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की हर योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल की उपस्थिति में शुक्रवार को राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बीच जल जीवन मिशन 2.0 अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधा सुलभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री

श्री पाटिल तथा राज्य के जलापूर्ति मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सहभागी हुए।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य के सुदूरवर्ती-दूरदराजी क्षेत्रों सहित हर कोने तक पर्याप्त स्वच्छ पेयजल पहुँचाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने जोड़ा कि सरकार द्वारा किया गया यह एमओयू राज्य के पेयजल प्रबंधन एवं ग्रामीण जनजीवन के गुणात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

श्री पटेल ने आगे कहा कि राज्य सरकार केन्द्र की हर योजना को प्राथमिकता के आधार पर सफल क्रियान्वयन करती है। जल जीवन मिशन 2.0 अंतर्गत हुआ यह एमओयू राज्य के ग्रामीण विकास में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। हर घर में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल पहुँचाने का संकल्प अब और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेगा।

जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त, 2019 को 'हर घर जल' के संकल्प के साथ की गई थी, जिसमें प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पीने का पानी पहुँचाने का उद्देश्य रखा गया था। गुजरात ने यह लक्ष्य अक्टूबर, 2022 तक सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, जो राज्य के लिए गौरव की बात है।

अब जल जीवन मिशन 2.0 अंतर्गत 2028 तक जलापूर्ति व्यवस्था का अधिक सुदृढ़ीकरण, नियमितता तथा सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करने का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इस एमओयू द्वारा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी तथा पारदर्शिता में वृद्धि होगी।

इस एमओयू के अनुसार राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर-निर्बाध एवं गुणवत्तायुक्त जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी तथा 'हर घर जल' प्रमाणपत्र प्राप्त करने के प्रयास अधिक वेगवान बनेंगे।

एमओयू अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं को समय पर तथा गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कर ग्राम पंचायतों को सौंपने, संचालन एवं रखरखाव (ओएण्डएम) सुनिश्चित करने, ग्रामीण स्तर पर विलेज वॉटर एंड सेनिटेशन समिति (वीडब्ल्यूएससी) द्वारा जल प्रबंधन का संचालन करने, जल स्रोतों की दीर्घकालीन सुरक्षा करने और सस्टेनेबिलिटी पर बल देने जैसे विषय शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त; डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए 'सुजलम भारत' तथा 'पीएम गति शक्ति' जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी। पानी की गुणवत्ता का निरीक्षण, वित्तीय अनुशासन, 'नल से जल मित्र' जैसी पहलों के माध्यम से मानव संसाधन विकास एवं जल संरक्षण के लिए 'जल उत्सव' जैसे अभियान भी इस मिशन का अभिन्न हिस्सा रहेंगे।

इस एमओयू के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों भी स्पष्ट की गई हैं। केन्द्र सरकार मार्गदर्शन, फंडिंग तथा मॉनिटरिंग करेगी; जबकि राज्य सरकार क्रियान्वयन, नीति सुधार तथा टेक्निकल सपोर्ट की जिम्मेदारी निभाएगी।

सप्ताह के दौरान सोना वायदा 15317 रुपये और चांदी वायदा 36502 रुपये लुढ़का: क्रूड ऑयल वायदा में 263 रुपये का ऊछाल

(जीएनएस)। मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 13 से 19 मार्च के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 4003907.95 करोड़ रुपये का उल्लेखनीय टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 355217.74 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 3648685.31 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मार्च वायदा 36981 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 61607.49 करोड़ रुपये का हुआ। आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 226392.33 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 160251 रुपये के भाव पर खुलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 160673 रुपये के उच्च और 141121 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 160271 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 15317 रुपये या 9.56 फीसदी लुढ़ककर 144954 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा सप्ताह के अंत में 12738 रुपये या 9.7 फीसदी औंधकर 118538 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 1638 रुपये या 9.93 फीसदी गिरकर सप्ताह के अंत में 14852 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 160411 रुपये के भाव पर खुलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 160749 रुपये के उच्च और 141089 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 15350 रुपये या 9.57 फीसदी लुढ़ककर 145017 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम सप्ताह के आरंभ में 161979 रुपये के भाव पर खुलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 161979 रुपये के उच्च और 141116 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 161359 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 15907 रुपये या 9.86 फीसदी की गिरावट के साथ 145452 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सप्ताह के आरंभ में 266001 रुपये पर खुलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में

ऊपर में 269186 रुपये और नीचे में 214212 रुपये पर पहुंचकर, 267962 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 36502 रुपये या 13.62 फीसदी लुढ़ककर 231460 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इसके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा सप्ताह के अंत में 36840 रुपये या 13.46 फीसदी गिरकर 236774 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 36741 रुपये या 13.42 फीसदी औंधकर सप्ताह के अंत में 236979 रुपये प्रति किलो पर आ गया। मेटल वर्ग में 29178.75 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा सप्ताह के अंत में 90.35 रुपये या 7.51 फीसदी औंधकर 1111.95 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता मार्च वायदा 18.75 रुपये या 5.76 फीसदी लुढ़ककर सप्ताह के अंत में 306.60 रुपये प्रति किलो बंद हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 19.5 रुपये या 5.57 फीसदी घटकर 330.45 रुपये प्रति किलो के भाव पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ। जबकि सीसा मार्च वायदा 2 रुपये या 1.06 फीसदी घटकर सप्ताह के अंत में 186.25 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 355217 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 3648685 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ साप्ताहिक टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 226392 करोड़ रुपये का हुआ साप्ताहिक कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 36981 पॉइंट के स्तर पर

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 99604.66 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स इलेक्ट्रिसिटी मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में प्रति एमडबल्यूएच 4980 रुपये के भाव से खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 5203 के उच्च और 4275 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में यह वायदा 480 रुपये या 10.05 फीसदी की गिरावट के साथ 4294 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 8830 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 9421 रुपये और नीचे में 8501 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 263 रुपये या 3.01 फीसदी की तेजी के संग 8998 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 264 रुपये या 3.02 फीसदी की बढ़त के साथ 8999 रुपये प्रति बैरल के भाव पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा 300.4 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 307.90 रुपये और नीचे में 271.4 रुपये पर पहुंचकर, 297.6 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 2.10 रुपये या 0.71 फीसदी गिरकर 295.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 2.20 रुपये या 0.74 फीसदी लुढ़ककर सप्ताह के अंत में 295.40 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बंद हुआ। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 990 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 21.20 रुपये या 2.13 फीसदी औंधकर 972.9 रुपये प्रति किलो पर आ गया। कॉटन मार्च वायदा सप्ताह के अंत में 760 रुपये या 2.95 फीसदी के ऊछाल के साथ 26520 रुपये के भाव पर बंद हुआ। इलायची मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में प्रति किलोग्राम 2521 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के अंत में यह वायदा 101 रुपये या 4.00 फीसदी की नरमी के साथ 2424 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 140514.63 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 85877.70 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 21370.04 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 4822.79 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 147.39 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 2781.75 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा इलेक्ट्रिसिटी वायदाओं में 211.04 करोड़ रुपये, क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 74317.08 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 25076.53 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 28.68 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन के वायदाओं में 10.22 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इलायची वायदा में 3.10 करोड़ रुपये के ट्रेड हुए।

सप्ताह के अंत में ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 6441 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 35386 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 11964 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 162971 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 25574 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 6312 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 15970 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 57448 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 19025 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 12661 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 39270 पॉइंट पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 39630 के उच्च और 36400 के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 3117 पॉइंट घटकर 36981 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने चेटीचंड के पवित्र त्योहार की शुभकामनाएँ देते हुए भगवान झूलेलाल की शोभायात्रा को प्रस्थान कराया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ सिंधी समाज ने साहस, परिश्रम तथा पुरुषार्थ से व्यापार-वाणिज्य सहित अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है

▸▸ गुजरात को अपनी मातृभूमि व कर्मभूमि बनाने वाले सिंधी समाज ने अपनी भाषा एवं पहचान बनाए रखते हुए दूध में चीनी की भाँति घुलकर राज्य के विकास में सक्रिय योगदान दिया है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को सिंधी समाज के भाइयों-बहनों को चेटीचंड के पवित्र त्योहार की शुभकामनाएँ देते हुए भगवान झूलेलाल की शोभायात्रा को प्रस्थान कराया। अहमदाबाद महानगर पालिका (मनपा) तथा चेटीचंड महोत्सव समिति द्वारा नरोडा पाटिया क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि चेटीचंड दरियादेव की आराधना का पवित्र त्योहार है और इसके साथ आज चैत्री नवरात्रि की उपासना का भी पावन अवसर है। उन्होंने कहा कि सिंधी समाज साहस, परिश्रम तथा पुरुषार्थ के लिए जाना जाता है और इस समाज ने व्यापार-वाणिज्य सहित अनेक क्षेत्रों में परचम लहराया है।

श्री पटेल ने आगे कहा कि सिंध से आकर गुजरात को अपनी मातृभूमि व कर्मभूमि बनाने वाले सिंधी समाज ने अपनी भाषा एवं पहचान बनाए रखते हुए गुजरात की संस्कृति में दूध में चीनी की भाँति घुलकर राज्य के विकास में सक्रिय योगदान दिया है। समाज की यह भावना 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के मंत्र को साकार करती है। उन्होंने जोड़ा कि नई पीढ़ी अपनी परंपरा तथा विरासत के साथ जुड़े; इसके लिए ऐसे धार्मिक एवं सामूहिक आयोजन महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अपील की कि सिंधी समाज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'कैच द रेन', 'एक पेड़ माँ के नाम' तथा 'स्वच्छ भारत' जैसे अभियानों में सक्रिय सहभागी बने।

इस अवसर पर विधायक डॉ. पायलबेन कुकरानी ने स्वागत संबोधन में कहा कि धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए सिंधी समाज ने अपने वतन सिंध को छोड़कर भारत को अपना घर बनाया और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

समारोह में शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रीवाबा जाडेजा, सांसद श्री दिनेशभाई मकवाणा व श्री हसमुखभाई पटेल, विधायक श्रीमती कंचनबेन रादडिया, पूर्व मंत्री श्री मायाबेन कोडनानी, पूर्व विधायक श्री निर्मलाबेन वाधवानी, सिंधी समाज के संत-महंत तथा भाई-बहन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा गुजरात वार्षिक अधिवेशन और 'गुजरात@1$ ट्रिलियन इकोनॉमी' विषय पर सम्मेलन का आयोजन

▸▸ गुजरात वैश्विक निवेशकों के लिए सर्वोत्तम डेस्टिनेशन बन गया है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अहमदाबाद में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की ओर से आयोजित गुजरात वार्षिक अधिवेशन और और 'गुजरात@1$ ट्रिलियन इकोनॉमी' विषय पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बनाई गई विकास की राह पर चलकर गुजरात 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार उद्योगकारों के साथ खड़े रहकर तमाम आवश्यक समर्थन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अतीत को याद करते हुए कहा कि एक समय था, जब गुजरात में विकास केवल वापी-वडोदरा बेल्ट तक ही सीमित था। लेकिन, प्रधानमंत्री ने पूरे गुजरात के सर्वग्राही विकास की सोच के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि 2003 से शुरू हुई वाइब्रेंट गुजरात समिट के चलते आज गुजरात वैश्विक निवेशकों के लिए सर्वोत्तम गंतव्य (डेस्टिनेशन) बन गया है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व पर अटूट विश्वास के कारण ही आज भारत और विशेषकर गुजरात में सेमीकंडक्टर जैसी अत्याधुनिक इंडस्ट्री आई है। जो काम दशकों तक असंभव प्रतीत होता था, वह आज गुजरात की धरती पर साकार हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने गुजरात की आर्थिक क्षमता का जिक्र करते हुए गर्व से कहा कि देश की केवल 5 फीसदी आबादी होने के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गुजारत की हिस्सेदारी 8 फीसदी है, जिसे हमें 10 फीसदी से ऊपर ले जाना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देश के कुल उत्पादन में गुजरात की हिस्सेदारी 17 फीसदी है जबकि देश के कुल निर्यात में गुजरात 33 फीसदी के योगदान के साथ शीर्ष पर है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 2001-02 में जिस एमएसएमई की संख्या 1.85 लाख थी, वह आज बढ़कर 27.9 लाख तक पहुंच गई है। वहीं, लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बात करें, तो देश के कुल कार्गो हैंडलिंग का 40 फीसदी हिस्सा अकेला गुजरात संभालता है। इसी प्रकार, क्षेत्रवार गुजरात की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि केमिकल उद्योग में 33 फीसदी, फार्मा एक्सपोर्ट में 19.2 फीसदी और डायमंड एक्सपोर्ट में 80 फीसदी हिस्सेदारी के साथ गुजरात देश में सबसे आगे है।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि गुजरात एक 'पॉलिसी ड्रिवेन स्टेट' यानी नीति-संचालित राज्य है। उद्योगकारों को उद्योग की स्थापना से लेकर संचालन तक के प्रत्येक चरण में क्लैरिटी यानी स्पष्टता मिले, इसके लिए स्पष्ट नीतियां बनाई गई हैं और समय की मांग के अनुसार इसमें आवश्यक बदलाव भी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात ने 2047 तक के 'विकसित भारत' का रोडमैप तैयार कर लिया है और उसे धरातल पर उतारने का कार्य भी शुरू हो चुका है।

औद्योगिक शक्ति से वैश्विक आर्थिक केंद्र बनने की ओर गुजरात के दृढ़ संकल्प पर आधारित इस कार्यक्रम में सीआईआई के वेस्टर्न रीजन के चेयरमैन श्री प्रेमराज कश्यप, वाइस चेयरमैन श्री अचल बकेरी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री गुरशरण सिंह सहित सीआईआई के पदाधिकारी और उद्योग जगत के अग्रणी मौजूद रहे।

नक्सलवाद पर सख्त प्रहार से बदला छत्तीसगढ़ का चेहरा, विकास को मिली नई रफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वर्षों से विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा रहे नक्सलवाद पर अब निर्णायक प्रहार होने का दावा राज्य सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि केंद्र और राज्य की "डबल इंजन" सरकार के समन्वित प्रयासों के चलते नक्सल समस्या अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है, जिससे राज्य में शांति, निवेश और विकास का नया दौर शुरू हुआ है। यह बयान उन्होंने अपने निवास कार्यालय में नेशनल डिफेंस कॉलेज के सैन्य और सिविल सेवा अधिकारियों के अध्ययन दल से मुलाकात के दौरान दिया।

मुख्यमंत्री ने देश-विदेश से आए अधिकारियों का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा और उसकी अपार संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों से बेहद समृद्ध है, जहां लगभग 46 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। कोयला, लौह अयस्क और हीरे जैसे खनिजों के विशाल भंडार के साथ-साथ लगभग 30 हजार मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत बनाती है। पिछले दो वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलना इस बात का संकेत है कि राज्य में निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है।

साय ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल बना है, जिसका सीधा असर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। सुरक्षा बलों की मजबूत रणनीति, आधुनिक तकनीक और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नक्सल गतिविधियों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है। उन्होंने कहा कि जहां पहले डर और असुरक्षा का माहौल था, वहां अब विकास की योजनाएं तेजी से लागू हो रही हैं।

नक्सलवाद के कमजोर पड़ने से राज्य में निवेश के नए दरवाजे खुल गए हैं। पहले जिन क्षेत्रों में उद्योग लगाने से निवेशक कतराते थे, अब वहां औद्योगिक गतिविधियों की संभावनाएं बढ़ रही हैं। सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बदलाव केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि जमीन पर महसूस किया जा सकता है, जहां लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है।

कृषि क्षेत्र का जिक्र करते हुए साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ को "धान का कटोरा" कहा जाता है और यहां किसानों के हित में कई प्रभावी योजनाएं लागू की गई हैं। राज्य सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीद 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कर रही है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह नीति किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'महतारी वंदन योजना' के तहत अब तक 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं को वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा 5.30 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

अध्ययन दल में शामिल विदेशी अधिकारियों ने भी छत्तीसगढ़ में हो रहे बदलावों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र की जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और वहां के लोगों की जीवनशैली को बेहद आकर्षक बताया। अधिकारियों का कहना था कि राज्य में सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन बनाकर जो मॉडल अपनाया गया है, वह अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणादायक हो सकता है।

एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी ने इस दौरान कहा कि मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट नीतियों के चलते छत्तीसगढ़ में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है, बल्कि आम जनता का भरोसा भी बढ़ा है।

मुख्यमंत्री साय ने अंत में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल नक्सलवाद का अंत करना नहीं, बल्कि एक ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे और विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल होगा।

कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही यह मुहिम अब केवल सुरक्षा अभियान नहीं रह गई है, बल्कि यह विकास, विश्वास और बदलाव की एक व्यापक प्रक्रिया बन चुकी है, जो राज्य के भविष्य को नई दिशा देने का काम कर रही है।

खाड़ी में जंग, घर की रसोई पर वार: महंगाई की आंधी में पिसता आम आदमी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब केवल अंतरराष्ट्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव भारत के आम नागरिक के जीवन पर दिखाई देने लगा है। हजारों किलोमीटर दूर हो रही जंग ने देश के बाजार, रसोई और जेब—तीनों पर एक साथ दबाव बना दिया है। पेट्रोल से लेकर दाल, तेल, सूखे मेवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहां तक कि इलाज तक—हर चीज महंगी होने की राह पर है, जिससे आम आदमी की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है।

सबसे पहले असर ईंधन की कीमतों पर पड़ा है। भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी सरकारी तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दाम में 2.09 से 2.35 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। भोपाल जैसे शहरों में इसकी कीमत करीब 117 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। हालांकि सामान्य पेट्रोल की कीमत अभी स्थिर है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक हालात ऐसे ही बने रहे, तो इसमें भी बढ़ोतरी संभव है।

ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर केवल वाहनों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव पूरी सप्लाई चेन पर पड़ता है। परिवहन महंगा होने से हर वस्तु की लागत बढ़ जाती है। इसी कड़ी में अब ऑनलाइन खाना मंगवाना भी महंगा हो गया है। Zomato ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे हर ऑर्डर पर अब उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। रोजाना लाखों ऑर्डर डिलीवर करने वाली इस सेवा के महंगे होने का असर शहरी उपभोक्ताओं पर तुरंत दिखने लगा है।

रसोई की बात करें तो आने वाले दिनों में दालों की कीमतों में 5 से 12 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, और शिपिंग लागत बढ़ने से अरहर, मसूर और चना दाल महंगी हो सकती है। इसी तरह खाद्य तेल की कीमतों में भी शुरुआती तौर पर 5 प्रतिशत और लंबे समय में 15 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर बढ़ती लागत का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ेगा।

सूखे मेवे इस महंगाई की सबसे बड़ी मार झेल सकते हैं। ईरान और मध्य एशिया से आने वाले बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट की कीमतों में 30 प्रतिशत तक उछाल आ सकता है। भारत हर साल भारी मात्रा में इनका आयात करता है, और परिवहन लागत बढ़ने से इनकी कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं। इसका असर खासकर त्योहारों और विशेष अवसरों पर ज्यादा महसूस होगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण भी इस संकट से अछूते नहीं हैं। मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज और एसी जैसे उत्पादों की कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जहाजों के रूट बदलने और माल ढुलाई की लागत में 20 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि ने इन उत्पादों को महंगा बना दिया है। इसका असर सीधे तौर पर उपभोक्ताओं के बजट पर पड़ेगा।

निर्माण और उद्योग क्षेत्र पर भी इस वैश्विक संकट का गहरा असर पड़ने वाला है। स्टील और मशीनरी की कीमतों में बढ़ोतरी से मकान निर्माण महंगा हो जाएगा। छोटे उद्योगों के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उनकी लागत बढ़ेगी और मुनाफा घटेगा। इससे रोजगार के अवसरों पर भी असर पड़ सकता है, जो पहले से ही आर्थिक दबाव में हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र भी इस महंगाई की चपेट में आ सकता है। भारत का फार्मा सेक्टर कच्चे माल के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। यदि कच्चा माल महंगा होता है, तो दवाइयों की कीमतों में 5 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है।

इसके अलावा, प्लास्टिक और पैकेजिंग सामग्री महंगी होने से दूध, बिस्किट और अन्य रोजमर्रा के उत्पादों की कीमतों में भी इजाफा होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में जारी यह संघर्ष लंबा खिंचता है, तो महंगाई की यह लहर और तेज हो सकती है। कुछ वस्तुओं की कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि भी संभव है। ऐसे में आम आदमी के लिए घर का बजट संभालना और कठिन हो जाएगा।

यह स्थिति इस बात को भी उजागर करती है कि वैश्विक घटनाएं किस तरह स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। आम नागरिक, जो इन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं होता, वही सबसे

पश्चिम रेलवे-रतलाम मण्डल

निविदा सूचना

M247GLRSG7BOGIE252633

DATE 19.03.2026

कार्य का नामः– WAG–7 लोको की बोगी फ्रेम का रिपेयर/ओवरहोलिंग। स्थानः मु. का. प्र./दाहोद प. रेलवे कार्यालय, **2. कार्य की अनुमानित लागतः–** Rs.1,25,76,907/-, **3. बयाना राशिः–** Rs. 2,51,600/-, **4. ई–निविदा जमा करने तथा खुलने की दिनांक तथा समयः–** ई–निविदा जमा करने की नियत दिनांक तथा समय 08.04.2026 को 14.30 बजे तक तथा ई–निविदा उसी दिन 15.00 बजे खोली जायेगी। **5. निविदा सूचना तथा प्रपत्र उपलब्धता :–** **www.ireps.gov.in** / E-Tenders / Works / IR Electrical.

17/1/518

हमें लाइक करें: **facebook.com/WesternRly**

In The High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh Judicial Department

RSA No. 2651 of 1985 (O&M)

Next date of hearing:- 08.04.2026

Kuldeep Singh (Deceased through Lrs)

Vs

Promila Rani and ors

Petition/Appeal U/s 151 C.P.C. and other relevant provision of C.P.C.

To,

Respondent No. 1

Smt Promila Rani Chaudhary wife of Sh. Sham Chaudhary, resident of Devan Iqbal Nath Colony, Karnal

In the above titled petition/appeal, the respondent (s)/defendant(s) could not be served in the ordinary process.

It is ordered that the respondent(s)/ defendant(s) should appear in person or through counsel on 08.04.2026 at 10 A.M. sharp. For details log on to www.highcourtchd.gov.in

Superintendent RSA
For Registrar Judicial
Punjab and Haryana High Court
Chandigarh

हिमाचल में सेवा विस्तार का खुलासा: 124 अफसर कर्मियों को मिली मंजूरी, सभी लंबित मामले निपटाए

शिमला। हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए सेवा विस्तार को लेकर राज्य सरकार ने विधानसभा में विस्तृत जानकारी साझा की है, जिससे प्रशासनिक फैसलों की पारदर्शिता पर जोर देने की कोशिश दिखाई देती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने बताया कि कांग्रेस सरकार के गठन के बाद शुरुआती सात महीनों में कुल 12 अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा विस्तार प्रदान किया गया। यह जानकारी विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई, जिसमें विस्तार से बताया गया कि किन-किन विभागों में यह निर्णय लिया गया।

सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, सेवा विस्तार मुख्य रूप से जरूरत और विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिया गया। इनमें सबसे अधिक मामले स्वास्थ्य विभाग से जुड़े रहे, जहां आठ अधिकारियों-कर्मचारियों को एक्सटेंशन मिला। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार, बहुउद्देश्यीय परियोजना एवं ऊर्जा, कार्मिक तथा श्रम एवं रोजगार जैसे विभागों में एक-एक अधिकारी को सेवा विस्तार दिया गया। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार ने उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी, जहां अनुभव और विशेषज्ञता की तत्काल आवश्यकता थी।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2024 के बीच विभिन्न विभागों की ओर से सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति के कुल 134 प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे गए थे। इन प्रस्तावों की गहन जांच और निर्धारित प्रक्रिया के पालन के बाद 124 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। वहीं, दो प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया, जबकि आठ मामलों में अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी, जिसके कारण वे कुछ समय के लिए लंबित रहे।

सरकार का दावा है कि सभी प्रस्तावों पर नियमानुसार विचार किया गया और किसी भी निर्णय में जल्दबाजी या पक्षपात नहीं किया गया। मुख्यमंत्री सुक्खु ने स्पष्ट किया कि सेवा विस्तार केवल उन्हीं मामलों में दिया गया, जहां विभागीय कार्यों की निरंतरता बनाए रखना आवश्यक था या फिर संबंधित अधिकारी का अनुभव विशेष रूप से उपयोगी माना गया।

महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 अगस्त 2024 तक सभी लंबित मामलों पर निर्णय ले लिया गया और वित्त विभाग में सेवा विस्तार से जुड़ा कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं रहा। यह प्रशासनिक दक्षता और समयबद्ध निर्णय लेने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आमतौर पर ऐसे मामलों में लंबी प्रक्रिया और देरी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार सरकार ने सभी मामलों को समय पर निपटाने का दावा किया है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किसी भी ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) को कैबिनेट रैंक नहीं दिया गया है। यह बयान उन अटकलों को खारिज करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनमें आरोप लगाए जाते रहे हैं कि विशेष पदों पर नियुक्त अधिकारियों को अतिरिक्त सुविधाएं या दर्जा दिया जाता है।

राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि सेवा विस्तार को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं कि क्या इससे नए अधिकारियों के अवसर प्रभावित होते हैं या नहीं। हालांकि सरकार का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह से जरूरत और योग्यता के आधार पर लिया गया है, न कि किसी अन्य कारण से।

विशेषज्ञों का मानना है कि सेवा विस्तार एक दोधारी तलवार की तरह होता है। एक ओर यह अनुभवी अधिकारियों की सेवाओं का लाभ उठाने का अवसर देता है, वहीं दूसरी ओर यह नए प्रतिभाशाली अधिकारियों के लिए अवसर सीमित कर सकता है। ऐसे में संतुलन बनाए रखना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होती है।

आस्था की आड़ में 'काला खेल': गुजरात के योग आश्रम से चला नकली नोटों का करोड़ों का रैकेट बेनकाब

(जीएनएस)। अहमदाबाद। आध्यात्म और योग की आड़ में चल रहे एक चौंकाने वाले 'काले कारोबार' का गुजरात पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसने न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंचाई है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में सूरत से संचालित एक कथित योग आश्रम से जुड़े नकली नोटों के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। इस मामले में स्वयंभू गुरु प्रदीप जोटांगिया समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 करोड़ रुपये से अधिक की नकली करेंसी बरामद की गई है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क सुनियोजित तरीके से पिछले करीब एक साल से संचालित किया जा रहा था। सूरत स्थित सत्यम योग आश्रम, जहां बाहर से योग और सेवा कार्यों का दावा किया जाता था, अंदर ही अंदर अवैध गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। आरोपी प्रदीप जोटांगिया आश्रम को बड़ा और प्रभावशाली बनाने के लिए भारी धनराशि जुटाना चाहता था। उसने पहले वैध तरीकों से फंड इकट्ठा करने की कोशिश की—पैम्फलेट छपवाए, सेवा कार्यों के नाम पर लोगों से चंदा मांगा और विज्ञापन भी दिए—लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली।

आर्थिक तंगी और महत्वाकांक्षा के दबाव में उसने एक खतरनाक रास्ता चुना। अपने कुछ करीबी अनुयायियों के साथ मिलकर नकली नोट छापने की साजिश रची गई। इस योजना को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी मुकुल उर्फ मुकेश नाम के आरोपी को दी गई, जिसने इस 'काले कारोबार' का तकनीकी हिस्सा संभाला। पुलिस के अनुसार, मुकेश ने चीन से विशेष प्रकार का कागज मंगवाया, जो असली नोटों जैसा दिखता था। इसी कागज पर हाई-क्वालिटी प्रिंटिंग के जरिए नकली

नोट तैयार किए जाते थे, जिससे आम लोगों के लिए असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता।

इस रैकेट का कारोबार भी बेहद सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा था। आरोपियों ने अहमदाबाद के एक व्यक्ति के साथ सौदा तय किया था, जिसमें 3 लाख रुपये की नकली करेंसी के बदले 1 लाख रुपये असली लिए जाते थे। यानी करीब 33 प्रतिशत की दर से यह अवैध व्यापार किया जा रहा था। यह उनकी पहली बड़ी डील बताई जा रही है, लेकिन जांच में यह भी सामने आया है कि इससे पहले करीब 28 लाख रुपये की नकली करेंसी बाजार में खपाई जा चुकी थी।

ताजा मामले में आरोपी सूरत से अहमदाबाद एक बड़े सौदे को अंजाम देने पहुंचे थे। उनके पास 2 करोड़ रुपये से अधिक की नकली करेंसी मौजूद थी, जिसे बाजार में उतारने की तैयारी थी। लेकिन इससे पहले ही अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को इस डील की भनक लग गई। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए छापा मारा और सभी आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जो अगर सफल हो जाता तो अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकता था।

गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपी भी कथित गुरु के अनुयायी बताए जा रहे हैं, जो उसके निर्देशों पर इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक, नकली नोटों के इस धंधे को लेकर कई बैठकें आश्रम और मुकेश के घर पर आयोजित की गई थीं, जहां योजना बनाई जाती और काम को अंजाम दिया जाता। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि पूरी तैयारी और रणनीति के साथ इस अपराध को अंजाम दिया जा रहा था।

फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 14 दिन के रिमांड की मांग की है, ताकि गहन पूछताछ के जरिए इस रैकेट के अन्य पहलुओं का पता लगाया जा सके। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस मामले में और भी लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है, जिनकी तलाश के लिए अलग-अलग टीमों का गठन कर जांच तेज कर दी गई है। साथ ही, दो अन्य फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है।

यह मामला केवल नकली नोटों के कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के उस पहलू को भी उजागर करता है, जहां आस्था और विश्वास का दुरुपयोग कर अपराध को अंजाम दिया जाता है। एक योग आश्रम, जहां लोग शांति और आध्यात्मिकता की तलाश में जाते हैं, वहां इस तरह की गतिविधियों का होना बेहद चिंताजनक है।

विशेषज्ञों का मानना है कि नकली करेंसी का कारोबार देश की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा होता है। इससे न केवल बाजार में अस्थिरता आती है, बल्कि आम लोगों का भरोसा भी कमजोर होता है। ऐसे में इस तरह के रैकेट का समय रहते पर्दाफाश होना बेहद जरूरी था।

फिलहाल, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। लेकिन यह घटना एक चेतावनी भी है कि अपराधी अब नए-नए तरीकों और स्थानों का इस्तेमाल कर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में सतर्कता और जागरूकता ही इस तरह के अपराधों से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है।

सूरत आरटीओ का फैसला विवादों में: शोरूमों में दोपहिया वाहनों के स्टॉक पर प्रतिबंध से डीलर नाराज

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। वर्तमान में चैत्र के पवित्र महीने में नए वाहनों की खरीद हो रही है, जिसमें दोपहिया वाहन मुख्य रूप से मध्यम वर्ग द्वारा खरीदे जाते हैं। ऐसे में सूरत आरटीओ के शोरूम में बहुउद्देशीय (प्रत्येक कंपनी के दोपहिया वाहन) वाहन न रखने के मनमाने और अहंकारी फैसले से शहर और जिले के उप-डीलरों में आक्रोश और असंतोष फैल गया है। चैत्र के पवित्र महीने में जब ग्राहकों की मांग बढ़ जाती है और चार पहिया वाहनों के साथ-साथ दोपहिया वाहनों की भी खरीद शुरू हो जाती है, तब आरटीओ के इस मनमाने और अहंकारी फैसले के कारण ग्राहकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

शोरूमों में रखे वाहन ग्राहकों को उनकी पसंद के रंग, मॉडल और कंपनी चुनने की सुविधा देने के लिए ही रखे जाते हैं। अब जब ग्राहकों के लिए शोरूमों में दोपहिया वाहन उपलब्ध ही नहीं हैं, तो वे अपनी पसंद का वाहन कैसे खरीदेंगे? फिर सवाल यह उठता है कि जब अन्य वस्तुएं ग्राहकों के लिए प्रदर्शित की जाती हैं और डीलर या उप-डीलर बहुउद्देशीय वाहन भी शोरूमों में रखते हैं, जिन्हें ग्राहक चुनकर खरीद सकते हैं, तो इसमें किसी भी कानून या आरटीओ नियमों का उल्लंघन नहीं होता है। यानी, शोरूम संचालक सरकार को गुमराह करने या सरकारी खजाने को कोई वित्तीय नुकसान पहुंचाने का कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। इस आम और स्पष्ट बात को जानते हुए भी, जिसमें किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होता, सूरत आरटीओ अधिकारियों ने मनमाने ढंग से मनगढ़ंत कानून जारी कर बहुउद्देशीय वाहनों के डीलरों/उप-डीलरों को निर्देश दिया है कि वे शोरूमों में वाहनों का स्टॉक न रखें, बल्कि केवल विभिन्न वाहनों की तस्वीरों के एल्बम रखकर ही व्यापार करें। इससे पिछले आठ महीनों से शहर और जिले के 250 से 300 सब-डीलरों को भारी परेशानी हो रही है और उन्हें आर्थिक और मानसिक नुकसान पहुंचा है। लोकतांत्रिक देश में तानाशाही जैसी व्यवस्था चलाकर आरटीओ अधिकारी क्या हासिल करना चाहते हैं?

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक तंगी के ऐसे कठिन दौर में, जब लोग शाम को गुजारा करने के लिए कड़ी मेहनत करने के बावजूद आर्थिक स्थिति में अन्य व्यवसाय करने को मजबूर हैं, और बहुउद्देशीय वाहन शोरूम लाखों रुपये का निवेश करके कारोबार कर रहे हैं, ऐसे में सूरत आरटीओ का यह मनमाना और मनमानी भरा फैसला किस हद तक उचित है? इतना ही नहीं, शहर के कुछ इलाकों में 10x10 की छोटी दुकानों में खुलेआम दोपहिया वाहन बिक रहे हैं, तो क्या आरटीओ अधिकारी किसी के इशारों पर कुछ खास इलाकों में ही आदेश लागू करके दोपहिया वाहन शोरूमों को परेशान नहीं कर रहे हैं? जब यह सवाल सोचने लायक है, तो इसका जवाब सिर्फ आरटीओ ही दे सकता है।

गांधीनगर के सड़क एवं परिवहन सचिव, गांधीनगर के सड़क एवं परिवहन आयुक्त और सूरत आरटीओ को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन देने के बाद, सूरत आरटीओ ने 18/12/2025 के अपने पत्र में कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 33 से 43 का उल्लंघन होना सत्य नहीं है। वास्तव में, आरटीओ अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन कर रहा है और शोरूम मालिकों को मनगढ़ंत कानून दिखाकर परेशान करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है।

मीठी ईद का महत्व: रमज़ान के बाद खुशियों, मिठाइयों और सद्भावना का त्योहार

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। रमज़ान का महीना रोज़े का पवित्र महीना है। इस त्योहार, ईद पर, दुनिया भर के मुसलमान प्रार्थना करने, भोजन बाँटने और खुशी व सद्भाव मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईद-उल-फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है? ईद के उत्सव का क्या महत्व है और इसका क्या अर्थ है? इसे "मीठी ईद" क्यों कहा जाता है? ईद-उल-फितर को अक्सर "मीठी ईद" कहा जाता है। यह नाम रोज़े के महीने के अंत का जश्न मनाने के लिए मीठे पकवान बनाने और खाने की परंपरा से आया है। रमज़ान के महीने में सुबह से शाम तक रोज़ा रखने के बाद, परिवार सेवया (सेवया खीर), खीर, शीर खुरमा और कई तरह की मिठाइयों का आनंद लेते हैं। यह खुशी, कृतज्ञता और आत्म-अनुशासन के बाद जीवन की मिठास का प्रतीक है। यह रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और सामाजिक संबंधों को मधुर और मजबूत बनाता है। ईद के शुभ अवसर पर, दक्षिण गुजरात विकास उपभोक्ता संरक्षण और अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष, छगनलाल मेवाड़ा, पूरे मुस्लिम समुदाय को ईद मुबारक की शुभकामनाएं देते हैं और अल्लाह सर्वशक्तिमान से सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं।

सूरह: सात साल और तीन महीने की आयशा ने भी रमजान के पूरे महीने में रोज़ा रखकर अल्लाह की इबादत की

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। रमजान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। युवा से लेकर बुजुर्ग तक, सभी लोग पूरे रमजान के महीने में रोज़ा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। सूरत के बदेखाचकला चौराहे के पास रहने वाले यास्मीन और शोएब मेमन की सात वर्षीय और तीन महीने की बेटी आयशा ने भी पूरे रमजान के महीने में रोज़ा रखकर अल्लाह की इबादत की है।

सूरत: पूर्व विधायक और सांसद अमरसिंह जिनाभाई चौधरी पर अवैध रूप से जमीन बेचने और निजी लाभ लेने का आरोप लगा है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। दक्षिण गुजरात के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद अमरसिंह जिनाभाई चौधरी तापी जिले के व्यारा जिले में गणेशजी मंदिर के पास शक्ति नगर बोथेल कॉलोनी में रहते हैं। वे पूर्व विधायक और पूर्व सांसद हैं। सरकार विधायकों और सांसदों को आजीविका के लिए व्यवसाय करने हेतु सरकारी जमीनें देती थी। अमरसिंह जिनाभाई चौधरी को भी सूरत में पूना कुम्भरिया रोड पर सरकार द्वारा जमीन आवंटित की गई थी। इसी दौरान उन्हें सूरत शहर को गैस आपूर्ति करने का जिम्मा सौंपा गया और उन्होंने एक गैस एजेंसी भी शुरू की। लेकिन सूरत शहर के तेजी से विकास और कपड़ा बाजारों के निर्माण के कारण जमीन की कीमतें बढ़ गईं और चूंकि यह सड़क से लगी जमीन थी, इसलिए अमरसिंह भाई ने जमीन बेच दी। साथ ही, विधायक और सांसद होने के नाते उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और दूसरों की जमीनों पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने अपनी जमीन बेचकर मुनाफा कमाया और दूसरे व्यक्ति को दस्तावेज देकर उसे अपनी जमीन बताया। उन्होंने अपनी जमीन के आसपास की जमीन को पेट्रोल पंप चलाने के लिए बेच दिया और उससे लगी हुई जमीन, जिसे अब अंबर हाउस के नाम से जाना जाता है, भी बेच दी। उन्होंने अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करते हुए उस जमीन पर कब्जा किया और उसे बेच दिया। इस प्रकार, अमर सिंह जिनाभाई चौधरी ने किसी अन्य व्यक्ति की वैध भूमि पर धन के लालच में लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया है। सरकार द्वारा व्यापार और रोजगार के लिए दी गई भूमि को भला कैसे बेचा जा सकता है? और किसी विधायक या सांसद के लिए किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर कब्जा करना और अपने पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके उसे बेचना उचित नहीं है। यदि कोई आम आदमी किसी अन्य व्यक्ति के घर और जमीन पर कब्जा कर लेता है, तो सरकारी व्यवस्था उसके खिलाफ भूमि हड़पने का मामला दर्ज करने में संकोच नहीं करती। स्थानीय प्रशासन ने पाया है कि अमरसिंहभाई जिनाभाई चौधरी ने अवैध रूप से किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर कब्जा किया है। और यह जानते हुए भी कि भूमि को अवैध रूप से अंबर हाउस को बेचा गया था, सरकारी प्रशासन ने अमरसिंह जिनाभाई चौधरी के खिलाफ भूमि हड़पने का मामला दर्ज नहीं किया है।नवसर्जन संस्कृति 2 5

सामान्य तौर पर, सरकार को आरक्षित श्रेणी के सांसदों और विधायकों के भरण-पोषण के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए और विधायक या सांसद से सरकार द्वारा प्राप्त पेंशन भत्ते को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए।

डिजिटल जुए पर कड़ा प्रहार: सरकार ने 300 अवैध बेटिंग वेबसाइट्स-एप्स किए ब्लॉक

(जीएनएस)। नई दिल्ली। ऑनलाइन सट्टेबाजी और अवैध जुए के बढ़ते नेटवर्क पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 300 अवैध वेबसाइट्स और मोबाइल एप्स को ब्लॉक कर दिया है। यह कार्रवाई डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने और गैरकानूनी वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान लगातार चल रहा है और आने वाले समय में और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक अब तक कुल 8,400 से अधिक ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, जो अवैध सट्टेबाजी और जुए से जुड़े हुए थे। इनमें से करीब 4,900 वेबसाइट्स और एप्स को ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू होने के बाद ब्लॉक किया गया है। इससे यह साफ होता है कि नए कानून के लागू होने के बाद इस दिशा में कार्रवाई की गति काफी तेज हुई है। जिन प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की गई है, वे बड़े स्तर पर अवैध लेनदेन, मनी लॉन्ड्रिंग और जुए को बढ़ावा देने में शामिल थे। इन वेबसाइट्स और एप्स के जरिए लाखों लोगों को लुभाकर उनसे पैसे वसूले जा रहे थे, जिससे न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा था, बल्कि कई लोग कर्ज और मानसिक तनाव की स्थिति में भी पहुंच रहे थे। सरकार का मानना है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स युवाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, जो तेजी से डिजिटल माध्यमों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों का सहारा लिया गया है। सरकारी एजेंसियां लगातार ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रख रही हैं और संदिग्ध प्लेटफॉर्म्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक कर रही हैं। इसके साथ ही, ऐसे प्लेटफॉर्म्स से जुड़े बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जा रही है, ताकि पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा सके।

सत्यमेव जयते
गुजरात सरकार

आदिवासी क्षेत्रों में पहुँचे विकास के लाभ अपार

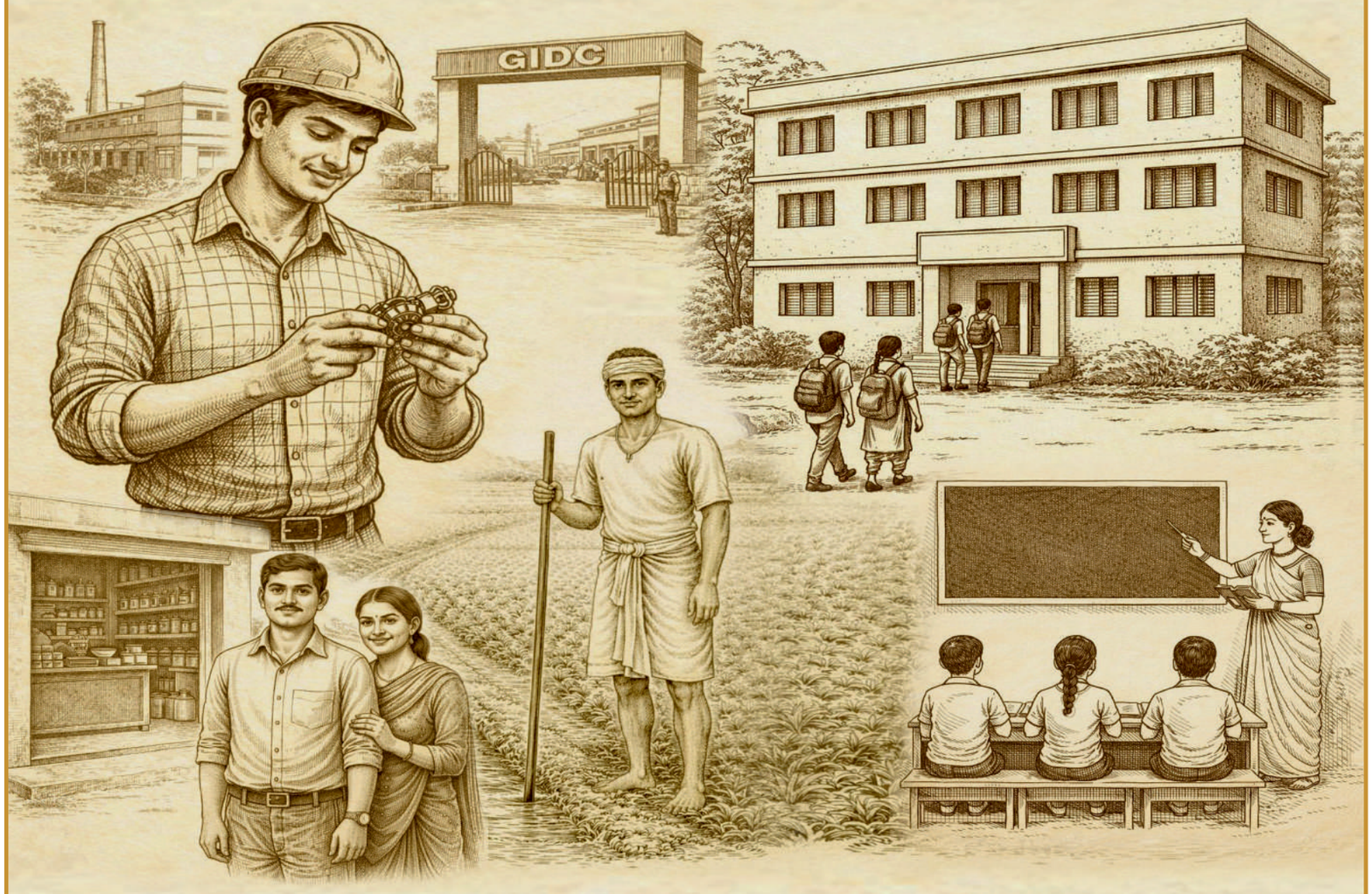

आदिवासी विकास विभाग के लिए
₹5,425 करोड़ का प्रावधान

विकसित भारत
गुजरात बजट 2026-27
विकसित गुजरात

- लगभग **2 लाख 35 हजार** विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ देने हेतु **₹909 करोड़** का प्रावधान
- **665** आश्रम विद्यालयों के **1 लाख** से अधिक विद्यार्थियों के लिए **₹595 करोड़** का प्रावधान
- सरकारी छात्रावास, आदर्श आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल तथा गर्ल्स लिटरेसी स्कूल के निर्माण हेतु **₹679 करोड़** का प्रावधान
- आदिवासी क्षेत्रों में उद्वहन सिंचाई योजना के लिए **₹485 करोड़** का प्रावधान
- आदिवासी क्षेत्रों के कुल **14** जिलों के **651** गांवों को कवर करने वाली **26** समूह जल आपूर्ति योजनाओं के लिए **₹280 करोड़** का प्रावधान
- आदिवासी क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहन और रोजगार बढ़ाने हेतु **5 GIDC** स्थापित किए जाएंगे
- आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी डॉक्टरों द्वारा स्पेशलिटी/मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल, जनरल नर्सिंग होम और डिस्पेंसरी स्थापित करने में सहायता प्रदान करने वाली स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए **₹22 करोड़** का प्रावधान।

"आदिजाति बंधुओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता देने वाला यह बजट 'आदिजाति बंधुओं के द्वार पहुंचे विकास के लाभ अपार' के हमारे संकल्प को चरितार्थ करेगा। जनजातीय समाज के सर्वांगीण उत्कर्ष से ही हम एक मजबूत और विकसित गुजरात का निर्माण कर रहे हैं।"

- श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात